

नं० एन०-३३/एन० एन०/१३-१४/९४.

७१९.

*U.S. Law*

*8*

*11/1994*



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राजशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १८ जुलाई, १९९४/२७ भाद्रपद, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(डी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-२, १ जून, १९९४

संख्या जी० ए० डी० ७ (जी०) १-१२/८१.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मूल नियमों के नियम ४५ और उन्हें सामर्थ्य बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवास आबंटन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

१. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, १९९४ है।

(2) यह नियम समस्त हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे।

(3) यह नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “आवंटन” से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग की अनुमति प्रदान करना अभिप्रेत है;

(ख) “आवंटन वर्ष” से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाला वर्ष या सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य अवधि अभिप्रेत है;

(ग) “वरीयता तिथि” वर्ग-4 और उससे ऊपर आवास के पात्र अधिकारी/पदधारी सम्बन्धी पूर्वािकता की तारीख ऐसी तारीख होगी, जब से वह राज्य सरकार या अन्यत्र सेवा/प्रतिनियुक्ति पर पद में विशेष वर्ग या उच्चतर वर्ग से सम्बद्ध परिलब्धियाँ निरन्तर ग्रहण कर रहा है;

परन्तु निम्न वर्ग के आवास का आवंटन आवेदक को उसकी प्रार्थना पर, यदि आवश्यक हो तो इस शर्त के अधीन दिया जाएगा कि वर्ग-4 और उससे ऊपर के आवास के हकदार राजनव्रित अधिकारियों को, राजनव्रित कर्मचारियों के लिए आवंटित किये जाने वाले आवास आवंटित नहीं किये जाएंगे:

परन्तु वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के आवास के लिये वरीयता तिथि, जब से अधिकारी/पदधारी राज्य सरकार की सेवा में निरन्तर कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा/प्रतिनियुक्ति भी है, उस वर्ग के लिए वरीयता तिथि होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी स्थिति में जब दो या उससे अधिक अधिकारियों/पदधारियों की वरीयता की तारीख एक ही हो तो ज्येष्ठता इस आधार पर अवधारित की जायेगी की तारीख उच्चतर परिलब्धियाँ प्राप्त करने वाले पदधारियों को उनसे कम परिलब्धियाँ प्राप्त करने वाले पदधारियों की अपेक्षा अधिकान दिया जायेगा और परिलब्धियाँ समान होने पर ज्येष्ठता सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी, और ऐसी स्थिति में जहाँ आवेदकों की सेवा भी अवधि भी एक समान है, उनके बीच ज्येष्ठता उनकी जन्म तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी और आयु में ज्येष्ठ आवेदक आवास के आवंटन के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ होगा।

(घ) “निदेशक” से हिमाचल प्रदेश के सम्पदा निदेशक तथा सम्पदा निदेशालय में निवृत्त सम्पदा अधिकारी जिन्हें उनके द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा, अभिप्रेत है;

(ङ) “सम्पदा अधिकारी” से जिला मुख्यालयों में नियुक्त सम्पदा अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) “पात्र कार्यालय” से हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जिसका कर्मचारीवृन्द हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन आवास आवंटन के लिए पात्र घोषित किया जा चुका है;

(छ) “परिलब्धियाँ” से मूल नियमों के नियम 9(21)(ए)(1) वर्णित केवल मूल वेतन अभिप्रेत है;

(ज) “परिवार” से पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो और वच्चे, सौतेले वच्चे, वैध रूप से दत्तक ग्रहण किये बच्चे, भाई या बहन जो प्रायः अधिकारी/पदधारी के साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं;

(झ) "आवास आवंटन समिति" से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर समिति अभिप्रेत है इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये कृत्यों को कार्यान्वयन करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ट) "अनुज्ञप्ति शुल्क" से कि सरकार द्वारा आवंटित किये जाने वाले आवासों के लिए समय-समय पर निर्धारित मासिक देय राशि अभिप्रेत है;

(ठ) "आवास" से आवंटन के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा उद्दिष्ट किये गये आवासों के सामान्य पूल में तत्समय सम्मिलित किये मकान अभिप्रेत हैं;

(ड) "पर किरायेदारी" से अभिप्रेत आबंटो द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ किराया लेने या न लेने पर साझा करना है;

परन्तु वह व्यक्ति यदि सरकारी आवास के आवंटन का हकदार है तथा उसे निदेशक द्वारा इस आशय की अनुमति दी गई है, जो इस शर्त पर दी जायेगी कि वह मिलने वाले सरकारी आवास भत्ते को नहीं लेगा और उसे इस साझीकरण के आधार पर उस आवास पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(ढ) "अस्थाई स्थानान्तरण" से ऐसा स्थानान्तरण अभिप्रेत है, जो चार मास की अवधि से अधिक न हो; और

(ण) "वर्ग" अधिकारी के सम्बन्ध में वर्ग से अभिप्रेत है, आवास की वह श्रेणी जिसका वह नियम 5 के अन्तर्गत पात्र है।

3. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं उनको आवास का आवंटन.—(1) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान हो, वह सरकारी आवास के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

(2) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित हो जाने के बाद वह अथवा उसके परिवार का अन्य सदस्य उसको ड्यूटी के स्थान पर या उसके समीप निजी मकान का मालिक बन जाता है, जो वह अधिकारी/कर्मचारी मकान को किराये पर देने अथवा उसमें निवास करने की तारीख से या मकान पूरा होने की तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो एक मास के भीतर इस बात की सूचना सम्पदा निदेशक/सम्पदा अधिकारी को देगा।

(3) अधिकारी/कर्मचारी, जिसका कि अपना या किसी अन्य सदस्य का अपनी ड्यूटी के स्थान पर या उसके समीप निजी मकान है और जिसे सरकारी आवास आवंटित है, तो उसे आवंटित सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियमों के नियम 45-ए तथा इससे सम्बन्धित जारी समय-समय पर आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत देय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में वर्णित परिवार से अभिप्रेत, अधिकारी/कर्मचारी के पत्नी/पति और आश्रित बच्चों से है।

4. अधिकारियों के विवाहित होने की स्थिति में आवंटन के लिए पति और पत्नी की पात्रता.—

(1) इस नियमों के अधीन किसी भी अधिकारी को तब तक आवास आवंटित नहीं किया जायेगा, जब तक यथास्थिति अधिकारी की पत्नी अथवा पति पहले से आवंटित किये गये आवास को खाली नहीं कर देता:

परन्तु यह उप-नियम उस पति और पत्नी पर लागू नहीं होगा, जो न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथक्करण आदेश के अनुसार अलग-अलग रह रहे हों।

(2) यदि दो अधिकारियों के पास इन नियमों के अधीन आबंटित अलग-अलग आवास हों और उनका एक दूसरे से विवाह हो जाए, तो वे विवाह के एक महीने के भीतर एक आवास खाली कर देंगे।

(3) यदि उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित आवास खाली नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर निम्न वर्ग का आवास रद्द हुआ समझा जाएगा। यदि आवास एक ही वर्ग के हों तो उनमें से एक का आबंटन निदेशक द्वारा उन्हें एक आवास छोड़ने के विकल्प का उचित मौका देकर अवधि की समाप्ति पर रद्द कर दिया जाएगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन नियोजित हैं; तो दोनों को आवास के आबंटन सम्बन्धी हकदारी पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) यदि यथा स्थिति पत्नी अथवा पति जो कि इन नियमों के अधीन आवास की/का आबंटित हो, को बाद में किसी अन्य पूल, जिस पर ये नियम लागू नहीं होते, से उसी स्थान पर आवास आबंटित किया जाता है, तो वह इस आबंटन के एक महीने के भीतर किसी भी एक आवास को खाली कर देगी/देगा।

परन्तु यह खण्ड ऐसे पति और पत्नी पर लागू नहीं होगा, जो न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथक्करण आदेश के अनुसार अलग-अलग रह रहे हैं।

(ख) यदि दो अधिकारियों को एक ही स्थान पर अलग-अलग आवास आबंटित किए गए हों अर्थात् एक को इन नियमों के अधीन आवास आबंटित किया गया हो और दूसरे को किसी अन्य पूल से आवास आबंटित किया गया हो, जिस पर यह नियम लागू नहीं होते और दोनों अधिकारियों का एक दूसरे से विवाह हो जाए, तो विवाह के एक महीने के भीतर उन दोनों में से कोई एक अपना आवास खाली कर देगा।

(ग) यदि खण्ड (क) अथवा (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार आवास खाली नहीं किया जाता तो सामान्य पूल से किया गया आवास का आबंटन इस अवधि के समाप्त होने पर रद्द किया गया समझा जाएगा।

5. आवास का वर्गीकरण.—इन नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय निम्न सारिणी में दर्शित वर्ग के आवास के आबंटन के लिए अधिकारी/पदधारी पात्र होंगे :—

आवास का वर्ग                      अधिकारी/पदधारी को प्रवर्ग या मासिक परिलब्धियां

1.	950.00 रुपये से कम
2.	1800/- रुपये से कम परन्तु 950/- रुपये से कम नहीं
3.	3000/- रुपये से कम परन्तु 1800/- रुपये से कम नहीं
4.	4500/- रुपये से कम परन्तु 3000/- रुपये से कम नहीं
5.	5900/- रुपये से कम परन्तु 4500/- रुपये से कम नहीं
6.	5900/- रुपये और उससे अधिक



6. आबंटन के लिए आवेदन.—(1) कोई अधिकारी/कर्मचारी जो आवास का आबंटन चाहता है या आवास को जारी रखना चाहता है, जो उसे आवंटित किया गया है, के लिए आवेदन निदेशक/सम्पदा अधिकारी को आवेदन, निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर देगा।

(2) प्रत्येक वर्ग के आवास के लिए वरीयता सूची प्रत्येक आबंटन वर्ष की पहली जनवरी को तैयार की जाएगी तथा उसे प्रत्येक त्रैमासिक अद्यतन किया जाएगा। पूर्ववर्त मास से मास की 15 तारीख तक प्राप्त आवेदन जब वरीयता सूचियां तैयार की जानी हैं अगली सूची तैयार की जाने की तारीख तक विधि मान्य होंगी।

(3) कोई अधिकारी/कर्मचारी जो उच्चतर वर्ग का पात्र हो जाता है, वह अपनी पात्रता के आवास के लिए पात्र होने की तिथि से 14 दिन के भीतर आवेदन दे सकता है।

7. आवास का आबंटन.—(1) यदि इन नियमों में अन्यथा 'उपबन्धित' न हो तो खाली आवास निदेशक द्वारा विशेष रूप से अधिमानतः ऐसे आवेदक को आवंटित किया जाएगा जो नियम 13 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन उसी वर्ग के आवास का इच्छुक हो तथा यदि वह आवाम उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो खाली आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे आवेदक को आवंटित किया जाएगा, जिसके पास उस वर्ग का आवाम न हो और जिसको वर्ग के आवास के लिए सबसे पहले पूर्वोक्ता तिथि हो :—

- (i) निदेशक ऐसे वर्ग के आवास का आबंटन नहीं करेगा, जो नियम 5 के अधीन आवेदक को पात्रता के वर्ग के आवास से बड़ा हो।
- (ii) निदेशक किसी आवेदक को ऐसा वर्ग स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो नियम 5 के अधीन उसकी पात्रता के वर्ग से छोटा हो।
- (iii) निदेशक निम्न वर्ग के आवास के आबंटन के लिए आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर उसे उसकी पात्रता से एक वर्ग निम्न का आवास आवंटित करेगा, जिसके लिए आवेदक पूर्वोक्ता की तारीख के आधार पर नियम 5 के अधीन पात्र हो।

(2) निदेशक किसी अधिकारी/कर्मचारी के मौजूदा आबंटन को रद्द कर सकता है तथा उसके लिए उसी वर्ग का वैकल्पिक आवास आवंटित कर सकता है अथवा आपातक परिस्थितियों में उस वर्ग से अगले निचले वर्ग का कोई वैकल्पिक आवास आवंटित कर सकता है, यदि अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अधिभोग वाले आवास को जनहित में खाली करवाना आवश्यक हो।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन किसी अधिकारी/कर्मचारी को आबंटन करने के अतिरिक्त खाली आवास प्राथमिकता के आधार पर अन्य पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जा सकता है।

8. बिना बारी से तदर्थ आबंटन.—नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी आवास आबंटन समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी को बिना बारी से निम्नलिखित आधार पर तदर्थ आबंटन किया जा सकेगा/जायेगा :—

(1) निम्नलिखित प्रकार की अस्वस्थता/बीमारी :—

(i) निम्नलिखित प्रकार से शारीरिक रूप से अयोग्य सरकारी कर्मचारी :—

(क) दृष्टिहीन अर्थात् जो निम्नलिखित किसी स्थिति से पीड़ित है :—

1. पूर्ण दृष्टिहीनता

2. संशोधक लैस तथाकर अच्छी आंख में दृष्टि की तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (तीक्ष्णता) से अधिक हो।
3. दृष्टि परतस 20 डिग्री के कोण को कक्षान्तरित कर रहा हो या अधिक दुरी हालत में है।

(ख) बधिर—वे व्यक्ति जिनको जीवन में सुनने के सामान्य प्रयोजन के लिए इन्द्रिय कोई कार्य नहीं करती हो। वे आवाज को विलुप्त सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते चाहें ऊंची आवाज में ही क्यों न बोला जाए। इन श्रेणियों में सम्मिलित किए गए वे मामले भी होंगे, जिनके अधिक अच्छे कान में 90 डेसिबल से अधिक श्रवण शक्ति की हानि हो गई हो या दोनों कानों से कुछ भी न सुनाई देता हो।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनके लिये अपनी विकलांग विरूपता के परिणामस्वरूप स्वतन्त्र रूप से चलना-फिरना बहुत कठिन हो गया हो।

(ii) हृदय रोगी (ग्रेड-3 और 4 लक्षणों वाले हृदय रोग, जिसके ग्रेड-3 और 4 का एन्जाइमा या ग्रेड-3 और 4 की संकुलित हृदय गति रुकना या ग्रेड-3 और 4 के लक्षणों सहित तीव्र अतिरिक्त दब जैसी गम्भीर आवश्यकतायें शामिल हैं।

(iii) क्षयरोगी (फुसफुस तपेदिक) सक्रिय अवस्था में जिसमें अन्य लोगों के लिये खतरा हो और कैंसर से पीड़ित कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति और उसके अभिन्न बच्चे।

(2) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसके सेवा निवृत्त होने पर, उसके पति/पत्नि या पुत्र या अविवाहित पुत्री को, यदि मृतक/सेवा-निवृत्त कर्मचारी को उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति के समय सरकारी आवास आवंटित था। ऐसा आवंटन मृतक/सेवा निवृत्त कर्मचारी के अभिभावक को उसकी पात्रता से उच्चतर वर्ग का आवास आवंटित नहीं किया जायेगा।

(3) आवंटि का स्थानान्तरण, विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जोकि सरकार द्वारा परियोजित हो, और अध्ययन अवकाश एक वर्ष से अधिक अवधि का हो, पर आवंटि के पति/पत्नि यदि वह उसी स्थान पर सरकारी सेवा में है, को उसकी पात्रता के अनुरूप।

(4) अधिकारी जो चिह्नित आवास में रह रहा है, का यदि उसी स्थान पर अन्य पद पर अथवा किसी दूसरे स्थान को स्थानान्तरण होने पर।

(5) अधिकारी/कर्मचारी जिनका जिला लाडौल स्थिति, किन्नीर और चम्बा जिला की तहसील पांगी में सेवा अवधि पूर्ण होने पर स्थानान्तरण हुआ हो।

(6) निजी कर्मचारी/वृन्द अर्थात् मन्त्रियों के निजी सहायक/निजी सचिवों आदि में से एक को।

(7) जहां सेवा की आकस्मिकतायें इस प्रकार समुचित ठहरायें।

(8) उप-नियम (1) से (7) में किसी बात के होते हुये भी अधिकारी/कर्मचारी जिनके अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसकी ड्यूटी के स्थान या उसके समीप मकान है, बिना बारी से तदर्थ आवंटन के पात्र नहीं होंगे।

(9) (i) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, के राज्य स्तरीय संवाददाताओं जिन्हें कि सरकार द्वारा प्रत्ययपत्र जारी किया हो तथा निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग द्वारा संस्तुति की गई हो, को यदि उन्हें आवास आवंटन करना न्यायोचित हो, को उनकी पात्रता जो कि केवल मूल वेतन (महंगाई भत्ते को छोड़कर) पर तय होगी, को केवल शिमला में आवास आवंटित किया जा सकेगा, परन्तु किसी

भी स्थिति में वर्ग-4 से ऊपरी वर्ग का आवास आवंटित नहीं किया जायेगा। ऐसा आवंटन केवल उन्हें किया जायेगा जिनका अपना अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम मकान नहीं है :

परन्तु संवाददाता जिन्हें पहले से आवास आवंटित है और वह अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम मकान का भाग लेता है/बनाता है/खरीदता है/बिरासत में पाता है, को तुरन्त आवंटित आवास छोड़ना होगा। संवाददाता द्वारा आवास आवंटन के समय इस आशय का शपथ-पत्र दिया जायेगा कि उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का शिमला अथवा उसके समीप कोई अपना मकान या किसी मकान का कोई भाग नहीं है और जैसे ही वह या उसका परिवार मकान प्राप्त कर लेता है या कोई मकान या मकान का कोई भाग बना लेता है, तो उनके तुरन्त बाद वह सरकारी आवास को खाली कर देगा :

परन्तु यह और भी कि इस उप-नियम के अन्तर्गत आवंटित संवाददाता को नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क तथा उन्हें उनके समाचार पत्र/समाचार एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला आवास भत्ता सरकार को देय होगा।

(ii) आवास आवंटन के लिये पूर्वांकता तिथि आवेदन करने की तिथि होगी।

(iii) एक समाचार पत्र/एजेंसी के संवाददाता को केवल एक ही आवास आवंटित किया जायेगा :

परन्तु इन नियमों के अधीन बिना बारी से तदर्थ आवंटन प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध आवासों के 50% से अधिक नहीं होगा। वर्ग-4 और उससे ऊपरी वर्ग के आवास प्रतिशतता निर्धारित करने हेतु इकट्ठे किये जायेंगे और उप-नियम (2), (3) और (9) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवंटन प्रतिशतता के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

9. आवंटन की अस्वीकृति या स्वीकृति के पश्चात् आवंटित आवास का अधिभोग रखने में असफल रहा.—

(1) यदि अधिकारी/कर्मचारी पांच दिन के भीतर आवास के आवंटन की स्वीकार करने में असफल रहता है या आवंटन के पश्चात् आवंटन के पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा नहीं लेता है, तो वह आवंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये अन्य आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि आवंटित आवास उसी प्रवर्ग का है, जिसके लिये वह हकदार है।

(2) यदि पात्रता से निम्न प्रवर्ग का आवास अधिभोग रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी को नियमों के अधीन उसकी पात्रता का आवास आवंटित किया जाता है, तो उसे उक्त आवंटन या आवंटन के प्रस्ताव का इन्कार करने पर निम्नलिखित शर्तों पर पहले आवंटित आवास में रहने की अनुमति होगी अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी/कर्मचारी आवंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्चतर वर्ग के आवास के लिये पात्र नहीं होगा।

(ख) विद्यमान आवास रखते समय उसे वही अनुज्ञप्ति शुल्क प्रदाय होगा, जितना उसने ऐसे आवंटित आवास की बाबत एफ0 आर0 45 ए या सम्बद्ध तत्स्थानी उप-नियम के अधीन सदस्त करना होगा या विद्यमान आवास की देय अनुज्ञप्ति शुल्क, जो भी अधिक हो, उस अवधि तक, जब तक कि उसे उच्चतर वर्ग के आवंटन के लिए वंचित किया गया है अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिये देय होगा।

(3) (क) अधिकारी/पदाधिकारी किसी भी समय सूचना देकर जो निदेशक के पास आवास खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व पहुंच जाये, आवंटन को अस्थगित कर सकता है। आवास का आवंटन निदेशक द्वारा प्राप्त पत्र के दिन से ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से जो भी बाद में हो, रद्द समझा जायेगा,

यदि वह सम्यक सूचना देने में असफल रहता है तो वह इस दिन के लिये या ऐसे दिनों के लिए जब तक उस द्वारा दी गई सूचना में इस दिन की कमी आती है, अनुज्ञप्ति शुल्क सदस्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि निदेशक कम अवधि के लिये सूचना स्वीकार करेगा।

(ख) कोई अधिकारी/पदधारी जो नियम 9 (3) के अधीन आवास को अभ्यर्पित करता है, उसकी बाबत ऐसे अभ्यर्पित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसी स्थान पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्पित करने की सूचना निम्नलिखित प्रकार के मामलों में आवश्यक नहीं है :—

- (1) जब कोई अधिकारी/पदधारी जो अपनी पत्नी के आवास से निम्न वर्ग के आवास का अभिभोग रखे हुये है,
- (2) जब कोई भी अधिकारी/पदधारी पुनः नियोजन पर आवास के निम्न वर्ग के आवास का हकदार पाया जाता है,
- (3) जब किसी अधिकारी/पदधारी को उसी वर्ग में आवास का परिवर्तन दिया जाता है,
- (4) जब अधिकारी/पदधारी के अभिभोग में आवास लोक प्रयोजनार्थ मुरम्मत, गिराये जाने के लिये अपेक्षित है,
- (5) जब अभिभोग में आवास का आबंटन, आबंटन नियमों के अधीन रद्द किया जाता है, या रद्द किया गया समझा जाता है,
- (6) जब सेवा निवृत्त/मृत आबंटि के पुत्र/पुत्री आदि वैकल्पित आवास प्राप्त कर लेते हैं।

10. अवधि जब तक आबंटन जारी रहता है और रियायती अवधि के लिये आगे रखा जाता है :—

(1) आबंटन आवास के अभिभोग की तारीख से या आबंटन पत्र की तारीख से पांच दिन तक जो भी पहले हो प्रभावी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि :—

(क) उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि के समापन पर अधिकारी का हिमाचल प्रदेश के पात्र कार्यालय में ड्यूटी बने न रहना,

(ख) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा रद्द किया जाता है या रद्द किया गया समझा जाता है,

(ग) अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित कर दिया जाता है, या

(2) अधिकारी को आबंटित आवास निम्न मारिणी के सतम्भ-1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से कोई घटना होने पर सतम्भ-2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि में लिये उप-नियम (3) के अधीन रहते हुये रखा जा सकता है, बशर्ते कि आवास अधिकारी के या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक प्रयोग के लिये अपेक्षित हो :—

घटनायें

1

आवास रखने के लिये अनुमत अवधि

2

(1) सेवा में दायवन्न, बहालितगी प्रयत्न निष्कामन, सेवा की समाप्ति प्रयत्न बिना अनुमति के अप्राधिकृत अनुस्थिति।

4 मास

(2) सेवा निवृत्ति अथवा सेवास्त अवकाश	4 मास
(3) स्थान से बाहर स्थानान्तरण	2 मास या उस तिथि तक जब तक कि नये तैनाती के स्थान पर आवास आवंटित नहीं होता, जो भी पहले हो।
(4) आबंटि की मृत्यु	1 वर्ष
(5) भारत में विभागेतर सेवा पर जाना	2 मास
(6) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत से बाहर किसी स्थान को स्थानान्तरण।	6 मास
(7) चिह्नित आवास का अभिभोग रखने वाले अधिकारी का स्थानान्तरण	प्रभार देने की तारीख से एक मास
(8) सेवानिवृत्ति से पूर्व छुट्टी, स्वीकृत छुट्टी, सेवास्त छुट्टी, चिकित्सा अवकाश (से भिन्न अवकाश)।	अवकाश की अवधि के लिये जो चार मास से अधिक नहीं
(9) अस्वीकृत छुट्टी की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी	अधिकतम चार मास के अधीन रहते हुए पूर्व चार मास की अवधि के लिये जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के समय अनुज्ञेय अवधि भी है।
(10) भारत से बाहर प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व की पूर्ण अवधि तक परन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं।
(11) भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश	अवकाश की अवधि के लिए जो छः मास से अधिक न हो।
(12) प्रशिक्षण पर जाना	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिये।
(13) प्रसूति अवकाश	प्रसूति अवकाश की अवधि के लिये तथा उसके साथ जोड़ी गई और छुट्टी जो कि अधिकतम पांच मास तक।
(14) चिकित्सा अवकाश जिसमें चार मास के बाद अस्पताल में भर्ती रहना पड़े।	पूरी अवधि तक के लिये।

नोटेशन-1.—मद 3, 6 और 7 के सन्ने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि प्रभार छोड़ने जना छुट्टी यदि कोई स्वीकृत हो और नये कार्यालय में पद ग्रहण करने से पूर्व ली गई छुट्टी से गणना की जाएगी।

नोटेशन-2.—यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना वेतन और भत्ता के चिकित्सा अवकाश पर हो तो वह उप-नियम (2) के नीचे दी गई शर्तों को मद (14) के अन्तर्गत दी गई शर्तों के आधार पर आवास की लाईसेंस फीम अदा करे और यदि वह दो महीने से अधिक समय तक इस प्रकार की लाईसेंस फीम अदा नहीं करता तो आवंटन रद्द हो जायेगा।

स्पष्टीकरण-3.—जहाँ आवास उप-नियम (2) के अधीन रखा गया है, अनुज्ञाप रिखायती अवधि की समाप्ति पर आर्बंटन रद्द समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-4.—कोई अधिकारी जिन पर नियम 2 की निम्न सारिणी के मद (1) और मद (2) के अधीन रिखायत होने के कारण रखा है, उक्त सारिणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयुक्त कार्यालय में पुनः नियोजन होने पर आवास को रखने का हकदार होगा और बहुतेक नियमों के अधीन आवास के और आर्बंटन के लिये भी पात्र होगा, परन्तु यदि ऐसे पुनः नियोजन पर अधिकारी की परिलब्धियाँ इनके द्वारा अधिभोग में आवास के लिये हकदार नहीं रहते, तो उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आवास आर्बंटन किया जायेगा :

परन्तु यह कि अधिकारी/कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा उप-नियम (2) में अनुमत्त अवधि के बाद छः मास की अवधि तक आवास दुगुने पूलड अनुज्ञप्ति शुरु पर रखने की अनुमति दी जा सकती है और यह भी कि अधिकारी/कर्मचारी को उसकी चरम अनुकम्पा परिस्थितियों में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसे और अवधि के लिये आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि किसी आर्बंटन का स्थानान्तरण शैक्षणिक मध्य सत्र में होता है और उसके वर्तमान तैनाती के स्थान पर बच्चे स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों तो ऐसे मामलों में गुणता के आधार पर और सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) उस आर्बंटन को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक आवास रखने की अनुमति दे सकेंगे। ऐसी अवधि का उप-नियम (2) में स्थानान्तरण और सेवानिवृत्ति पर अनुपलब्ध अवधि के बाद की अवधि के लिये दुगुना पूलड अनुज्ञप्ति शुरु देय होगा :

परन्तु यह भी कि अधिकारी/कर्मचारी जो कि भारत से बहरविदेश सेवा और प्रतिनिधित्व पर, भारत या विदेश में अथवा अवकाश पर जा रहे हों तो उक्त सम्बन्धित विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व अनुमति से अधिकारी/कर्मचारी के अर्शों की शर्तों में इन शर्तों का आवास करेंगे कि वह सरकारी आवास तभी रख पायेंगे यदि उनके परिवार के सदस्य आवास का वास्तविक अधिभोग करेंगे :

परन्तु यह और भी कि अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें कि सरकारी आवास आवंटित हो इस आशय का शपथ पत्र भी देंगे कि उनके परिवार के सदस्य आवास का वास्तविक अधिभोग करेंगे और यदि किसी समय यह पाया गया कि आवास का अधिभोग वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं लिया जा रहा है तो सरकार किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही जो इसके विरुद्ध की जा सकेगी, के प्रतिफल प्रभाव बिना आवास का आर्बंटन रद्द कर सकेंगी।

(3) यदि सेवा निवृत्ति के तत्काल पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी आवास रखने की अनुमत्त अवधि का लाभ नहीं उठाता है तो उसे पुनः नियोजन की अवधि पूरी करने के बाद उप-नियम (2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार रिखायती अवधि में आवास रखने की अनुमति दी जा सकती है। यदि पुनः नियोजन से पूर्व अधिकारी का अनुमत्त अवधि के कुछ भाग का लाभ दिया जा चुका है, तो उसे पुनः नियोजन की समाप्ति के पश्चात् आवास रखने की अनुमत्त अवधि के शेष भाग की अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

(4) अधिकारी/कर्मचारी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पदावधि पद पर नियुक्त किये जाते हैं, को उप-नियम (2) के अन्तर्गत दी जाने वाली अवधि तक आवास रखने के पात्र नहीं होंगे और ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को आर्बंटन सरकारी आवास पदावधि पद की अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन की अवधि में खाली करना होगा।

11. अनुज्ञप्ति शुरु का भुगतान.—(1) जहाँ आवास या वैकल्पिक आवास के आर्बंटन को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति शुरु देने का दायित्व प्रथमभोग की तारीख से या आर्बंटन पत्र की प्राप्ति के आठवें दिन की तारीख से जो भी पहले हो प्रारम्भ होगा।

(2) कोई अधिकारी/कर्मचारी जो स्वीकृति के पश्चात् आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उससे ऐसी तारीख से 12 दिन की अवधि के लिए या तारीख तक जो भी पश्चात्पूर्वती हो, जब वह स्वीकृति वापिस लेता है, से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।

(3) जहाँ कोई अधिकारी/कर्मचारी जो आवास के अधिभोग में है और उसको अन्य आवास आबंटित किया जाता है और वह नये आवास का कब्जा ले लेता है तो पूर्ववर्ती आवास का आबंटन नये आवास के अधिभोग करने की तारीख से रद्द समझा जायेगा। यद्यपि वह नये आवास के अधिभोग के पश्चात् दो दिन तक बिना किराया दिये पूर्ववर्ती आवास को रख सकता है।

12. आवास खाली किए जाने तक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने और स्थाई अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभू प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व—(1) जिस अधिकारी/कर्मचारी को आवास आबंटित किया गया है, जब तक उस आवास में वह रहता है या जब तक आवास उसको आबंटित रहता है, तक की अवधि की अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने और आवास तथा उसमें उपलब्ध करवाये गये फर्नीचर इत्यादि अथवा साज-सज्जा की उचित देख-भाल न करने के कारण देय क्षति की राशि का भुगतान करने का उसका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

(2) जिस अधिकारी/कर्मचारी को आवास आबंटित किया जाता है, यदि वह न तो स्थाई कर्मचारी है या स्थायीकृत नरकारी कर्मचारी, तो उस उस आवास और उसके बदले में आबंटित आवास के सम्बन्ध में देय अनुज्ञप्ति शुल्क और अन्य प्रभारों के भुगतान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए फार्म में एक प्रतिभूति बन्द पत्र प्रस्तुत करना होगा और उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी स्थाई कर्मचारी को प्रतिभूति के रूप में घोषित करना होगा।

(3) यदि प्रतिभू, सरकारी सेवा में नहीं रहता है या अपनी प्रत्याभूति वापिस ले लेता है या किन्हीं अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होता है, तो अधिकारी ऐसे तथ्य का ज्ञान होने की तारीख से तीस दिन के भीतर दूसरी प्रतिभू निष्पादित करवायेगा, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसके आवास का आबंटन जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए, तथ्य की तारीख से रद्द किया समझा जायेगा।

13. आवास में परिवर्तन—(1) अधिकारी/कर्मचारी जिसको इन नियमों के अधीन आवास आबंटित किया गया है, वह उसी वर्ग के आवास के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा। एक स्थान पर तेनाती के दौरान समवर्ग आवास में एक परिवर्तन से अधिक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, परन्तु अधिवर्षता की तारीख से छः मास की अवधि में किसी आवास के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) परिवर्तन, निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में उसके लिए प्राप्त आवेदनों के क्रमानुसार दिये जायेंगे।

(3) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी, उसे प्रस्तावित आवास के परिवर्तन की, ऐसे प्रस्ताव या आबंटन के जारी होने की तिथि से आठ दिन के अन्दर स्वीकार नहीं करता है, तो उस वर्ग के आवास के परिवर्तन हेतु पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

(4) आवास आबंटन समिति द्वारा असाधारण परिस्थितियों में दूसरे परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी।

14. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन—नियम 13 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अधिकारी/कर्मचारी को परिवार के सदस्य की मृत्यु पर आवास के परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी, यदि वह ऐसी घटना के तीन मास के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता है:

परन्तु परिवर्तन अधिकारी/कर्मचारी को पहले आबंटित वर्ग के आवास में ही दिया जाएगा।

15. आवास की पारस्परिक बदला-बदली.—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन एक ही वर्ग के आवास आबंटित किए गए हैं, वह अपने आवास की पारस्परिक बदला-बदली की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि दोनों अधिकारियों/कर्मचारियों से युक्तमंगल रूप से यह उमीद की जाती है कि वे ऐसी बदला-बदली के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छः महीने तक एक ही स्थान पर तैनात रहेंगे और अपने पारस्परिक बदला-बदली किए गए आवास में रहेंगे तो उन्हें पारस्परिक बदला-बदली की अनुमति दी जा सकती है।

16. ऐसी जगह स्थानान्तरण जहाँ परिवार भी नहीं रखा जा सकता.—यदि अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है, जहाँ उनको अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं है या सरकार द्वारा न रखने का परामर्श दिया गया है और इन नियमों के अधीन उसको आबंटित आवास उसके परिवार के सद्भाविक प्रयोग के लिए अवेक्षित है तो उसकी प्रार्थना पर साधारण अनुज्ञप्ति गुप्त संकेत करने पर आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी।

17. आवास का संरक्षण करना.—कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उसको आबंटित आवास को, जिसके अन्तर्गत आऊट हाऊसिंग, गैराज और अस्तबल जो उसके अनुलग्नक हैं, संभाल नहीं करेगा, जब तक कि वह सरकार द्वारा ऐसे करने के लिए प्राधिकृत न हो।

(2) निकट रिश्तेदारी के साथ संरक्षण करने पर किरायेदारी/संरक्षण नहीं सगृह्य जाएगा। निम्नलिखित रिश्ते घनिष्ठ रिश्तेदार समझे जाएंगे, जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, पोते, पोतियाँ, भ्रूज, चाटी, धबेरा भाई बहिन, भतीजे-भतीजी, जो शाही से सीधे रूप में खून के रिश्ते से सम्बन्धित हैं, समुर/माम, ननद, दामाद, बहू और कोई अन्य रिश्तेदारी, जो कि न्यायाधिक रूप से स्थापित हो।

18. आबंटन रद्द करने की शक्ति.—(1) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसको आवास आबंटित किया गया है, आवास को किरायेदारी में देता है या आवास के किसी भाग में अनाधिकृत निवास करता है या किसी भाग का प्रयोजन के लिए रखे प्रयोजन से भिन्न, किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है या विद्युत और जल कनेक्शन से छेड़छाड़ करता है या नियमों या तथा आबंटन के निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या आवास का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है, जिसको सरकार अनुचित समझती है या इस प्रकार का आचरण करता है, जो सरकार की राय में पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण नाता बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जिसने आबंटन प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन या लिखित ब्यान में गलत सूचना दी है, की सरकार किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, के प्रतिकूल प्रभाव बिना आवास के आबंटन को रद्द कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के अभिव्यक्ति “अधिकारी/कर्मचारी” के अन्तर्गत, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके परिवार का सदस्य और अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी, नियम-3 से तथा उपबन्धित निदेशक/सम्पदा अधिकारी की जानकारी अधिसूचित करने में असफल हुआ है या ऐसी जानकारी अधिसूचित करते समय उसने किसी आवेदन या कथन में तात्त्विक तथ्य को छिपाया है तो निदेशक उसके आबंटन को रद्द कर सकेगा।

(3) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों के उल्लंघन में किसी आवास या उसके किसी भाग को पर किरायेदारी पर देता है तो उसे किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अतः अधिकारिता प्रभाव्य होगा।



(4) जहाँ आबंटन आबंटनी द्वारा आवास को पर किराएदारी करने पर रह करना हो, आवास को खाली करने के लिए आबंटनी या उसके साथ रह रहे व्यक्ति को सात दिन की अवधि दी जाएगी। आबंटन आवास के खाली करने की तिथि से या आबंटन के रद्दीकरण के आदेशों की तारीख से सात दिनों की अवधि की समाप्ति से जो भी पहले हो, को कर दिया जाएगा।

(5) जहाँ पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आचरण के लिए आबंटन रद्द किया गया है, सरकार के विवेकाधिकारी से उसे अन्य आवास उसी वर्ग में किसी अन्य स्थान पर आबंटित किया जा सकेगा।

18 अ. सामान्य पूल आवास के अवधि अधिमोर्गियों द्वारा क्षत अधिमोर्ग हजाने की अनुज्ञप्ति शुल्क की बसुली.—(1) जब इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अधीन आबंटन रद्द किया जा चुका है या रद्द समझा गया है, उसके पश्चात् ऐसा आवास जिसको आबंटित किया गया था, के अधिमोर्ग या उसके माध्यम से बाधा करने वाले व्यक्ति के अधिमोर्ग में रहता है, तो ऐसा अधिकारी/कर्मचारी से आवास के प्रयोग और अधिमोर्ग, सेवाएं, फर्नीचर और बगीचा प्रभाग के लिए 4/- रुपये प्रति वर्गफुट की दर से क्षत अधिमोर्ग देय होगा।

स्पष्टीकरण.—“सेवाएं” के अन्तर्गत सफाई, सामान्य विजली और सामान्य जल सुविधा है।

(2) सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के अर्जित अवकाश के बदले देय वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके द्वारा आबंटित आवास यदि कोई है, को खाली नहीं कर देते। अर्जित अवकाश के बदले देय राशि उस अधिकारी के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति उपरान्त निहाल करके उसे सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के नाम 4 मास की अवधि के लिए एफ0 डी0 आर0 में रखी जाएगी, जो कि उप-नियम (1) के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास घरोहर बतौर क्षत अधिमोर्ग हजाने के प्रति समानत रहेंगी।

19. कतिपय श्रेणियों के अधिकारियों के लिए अलग-अलग पूल बनाना.—(1) इन नियमों में उल्लिखित किसी वर्ग के होते हुए भी निम्नलिखित पूल बनाए जाएंगे यथा :—

1. महिला अधिकारियों/कर्मचारियों का पूल
2. पारगमन आवास पूल
3. पदावधि अधिकारी/कर्मचारी पूल

(2) इन पूलों के अन्तर्गत रखे जाने वाले आवासों की संख्या तथा वर्ग का निर्धारण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन आवासों के आबंटन के लिए पात्रता अधिकारियों/कर्मचारियों की परस्पर बरिष्ठता निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाएगी यथा :—

(क) महिला अधिकारी/कर्मचारी पूल में आवास आबंटन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत पूर्वाता की तिथि के आधार पर पात्रता से एक वर्ग कम के आवास के आबंटन के लिए पात्र होगी।

(ख) पदावधि अधिकारी/कर्मचारी पूल में, उन तारीख के आधार पर जिस तारीख से ऐसे प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी ने उस वर्ग से सम्बन्धित परिलब्धियां प्राप्त करना आरम्भ किया हो, जिस वर्ग के आबंटन के लिए उस पर विचार किया जाना है।



(4) दो कमरे वाला आवास  
(प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिये)

100 रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी.—आवासों में अतिरिक्त प्रावधान सुविधाओं यथा फर्नीचर, गीजर इत्यादि के लिये अतिरिक्त प्रभार देय होंगे। पानी और बिजली के प्रभार के भुगतान के लिये आबंटित सम्बन्धित विभाग/निगम के प्रति उत्तरदायी होगा।

20. इन नियमों के जारी होने से पूर्व किये गये आबंटनों का जारी रहना.—आवास के ऐसे वृद्ध आबंटन जो इन नियमों के लागू होने से पहले जारी रहा हो, इस समय प्रवृत्ति निरमों के अन्तर्गत दृष्ट वास्तव के होते हुये भी कि वह अधिकारी जिस वह आबंटन किया गया है, सम्बद्ध नियमों के तहत उस वर्ग के आवास का हकदार नहीं है, इन नियमों के अधीन समायोजन से किया गया आबंटन समाप्त जायेगा और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती प्रावधान तदनुसार उस आबंटन और उस अधिकारी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

21. नियमों का निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वाचन की वास्तविकता कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शक्तियाँ या कार्य प्रत्यायोजित करना.—(1) सरकार नियमों द्वारा उसको प्रदत्त किसी शक्ति या शक्ति, केवल नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने की छोड़कर, उसके नियन्त्रणाधीन किसी भी अधिकारी को ऐसी शक्तों के अधीन जैसी कि वह अधिकारित करना उचित समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) निवेशक इन नियमों में प्रदत्त शक्तियों में से सभी अथवा उनमें से किसी को सम्बन्धित जिलों के सम्पदा अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है:

परन्तु इन नियमों के नियम 24 के अधीन शक्तियाँ किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेंगी।

23. अधिकारी/कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास और विभागीय पूल आवास के पात्र हैं, को आबंटन.—अधिकारी/कर्मचारी जो कि किराया मुक्त आवास तथा अधिकारी/कर्मचारी जिनके विभाग के अपने विभागीय पूल आवास हैं, वह सामान्य पूल से आवास आबंटन के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यह भी कि उन स्थानों पर जहाँ ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के लिये विभागीय पूल आवास सुविधा नहीं है तो वह उस स्थान पर अन्य पात्र पदधारियों सहित सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिये पात्र होगा। अधिकारी/कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास का पात्र है, को सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिए इस शर्त के साथ कि यदि उसे आवास आवंटित किया जाता है तो अनुसूचित शुल्क उसके सम्बन्धित विभाग द्वारा देय होगा, विचार किया जायेगा।

24. नियमों में छूट.—सद्व्यवहार, लिखित कारणों को लिपिबद्ध करके, लोचन में या प्रतिबोधक अनुकम्पा के मामलों में इन नियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

25. निरसत और व्यावृत्ति.—(1) हिमाचल प्रदेश सरकार निवास स्थान आबंटन नियम, 1986 एतद्वारा निरसत किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किया गया कोई आदेश, आबंटन या की गई कोई कार्यवाई या बात इन नियमों में अतिरिक्त तत्स्थानों उपबन्धों के अधीन की गई समझी जावेगी।

आदेश द्वारा,

एस० एस० नेगी,  
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English Text of Government Notification No. GAD-7 (G) 1-12/81, dated 1-6-94, as required under Clause (3) of Article 344 of the Constitution of India].

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### (D-SECTION)

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 1st June, 1994*

No. GAD-7 (G) 1-12/81.—In pursuance of Rule 45 of the Fundamental Rules and 'all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for the purpose of allotment of Government residences in Himachal Pradesh :

1. *Short title, commencement and application.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool), Rules, 1994.

(2) These shall apply to the whole of State of Himachal Pradesh.

(3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definition.*—In these rules, unless the subject of context otherwise requires :—

(a) 'allotment' means the grant of licence to occupy a residence in accordance with provisions of these rules;

(b) 'allotment year' means the year beginning on 1st January or such other period as may be notified by the Government;

(c) 'date of priority' of an officer/official in relation to type-IV and above residences shall be the date from which he has been continuously drawing the emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the State Government or on foreign service/deputation:

Provided that allotment of lower category residence may be made to an applicant at his request if considered necessary subject to the condition that the Gazetted Officers entitled to type-IV and above accommodation will not be allotted house meant for non-gazetted officials :

Provided further that in respect of type-I, type-II and type-III residences, the date from the officer/official has been continuously in service under the State Government including the period of foreign services/deputation shall be his date of priority for that type:

Provided further that where the date of priority of two or more officers/officials is the same, seniority amongst them shall be determined by the emoluments; the officer/official in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer/official in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal, by the length of service; and where both the emoluments and length of service are equal, seniority among them shall be determined by taking into consideration the date of their births and the applicant senior in age will be senior for the purpose of allotment of accommodation;

(d) 'Director' means Director of Estates, Himachal Pradesh and shall include Estate Officer posted in the Directorate of Estates authorised by him in this behalf;

(e) 'Estate Officer' means Estate Officers appointed by the State Government at the District Headquarters;

(f) 'eligible office' means a Himachal Pradesh Government Office, the staff of which has been declared by the Himachal Pradesh Government as eligible for accommodation under these rules;

(g) 'emoluments' means the basic pay only as defined under F. R. 9(21) (a) (i);

(h) 'family' means the wife or husband, as the case may be and children, step children, legally adopted children, parents, brothers and sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer official;

(i) 'house allotment committee' means a committee constituted by the Himachal Pradesh Government from time to time to carry out the functions assigned to it in these rules;

(j) 'Government' means the Himachal Pradesh Government unless the context otherwise requires;

(k) 'licence fee' means a sum payable monthly as fixed by the Government from time to time in respect of residence allotted by the Government under these rules;

(l) 'residence' means any residence included for the time being in the general pool of residences earmarked by the Government for the purpose of allotment;

(m) 'subletting' means sharing a residence by an allottee with another person with or without payment of rent;

Provided that an officer official of the Government eligible for allotment of Government residence can share the accommodation with the permission of the Director who shall permit such officer official sharing of accommodation on his surrendering his house rent allowance payable to him, but in no case such sharing shall entitle the shares to claim any right over the residence;

(n) 'temporary transfer' means a transfer of an officer official which involves an absence of a period not exceeding four months;

(o) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under rule 5.

3. *Allotment to house owning officers/officials.*—(1) Officer/Official owning a house in his own name or in the name of any member of his family shall be eligible for allotment of Government accommodation.

(2) When after a Government residence has been allotted to an officer/official, he or any member of his family becomes owner of a house at or near the place of his duty, such officer official shall notify the fact to the Director of Estates/Estate Officer within a period of one month from the date the house is let out or occupied, or the date of completion, whichever is earlier.

(3) An officer/official who owns a house either in his own name or in the name of any member of his family member at or near the place of his duty and allotted a Government accommodation shall be liable to pay the licence fee in accordance with the provisions of rule 45-A of Fundamental Rules and orders/instructions issued by the Central Government thereunder from time to time.

*Explanation.*—For the purpose of this rule member of family means the wife or husband as the case may be or a dependent child of the officer/official.

4. *Allotment to husband and wife eligibility in case of officers who are married to each other.*—(1) No officer/official shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband as the case may be, of the officer/official has already been allotted a residence unless such residence is surrendered; Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by a Court.

(2) Where two officers/officials in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of marriage surrender one of the residence.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residence are of the same type, the allotment of such one of them as the Director, after giving reasonable opportunity to exercise option, may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Himachal Pradesh Government, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (4) above :—

(a) If a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, he or she, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment:

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any Court.

(b) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

(c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b), the allotment of the residence in the general pool shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

5. *Classification of Residences.*—Save as otherwise provided by these rules officers/officials will be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below :—

Type of residence.	Category of officer/official or monthly emoluments drawn by the officer/official
I	Less than Rs. 950/-
II	Less than Rs. 1800/- but not less than Rs. 950/-
III	Less than Rs. 3000/- but not less than Rs. 1800/-
IV	Less than Rs. 4500/- but not less than Rs. 3000/-
V	Less than Rs. 5900/- but not less than Rs. 4500/-
VI	Rs. 5900/- and above.

6. *Application for allotment.*—(1) An officer/official who seek an allotment of residence and for the continuance of accommodation which has been allotted to him shall apply in that behalf to the Director/Estate Officer in a form as may be prescribed by the Director from time to time.

(2) The seniority list for each category of accommodation will be drawn on 1st January of each allotment year shall be updated quarterly. The applications received upto 15th of the month preceding the month when the seniority lists are to be drawn up will be valid till the next list is out.

(3) An officer/official who becomes eligible for higher type of accommodation may apply for the same within fourteen days from the date of such eligibility.

7. *Allotment of residence.*—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, falling vacant, will be allotted by the Director preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type, under the provisions of sub-rule(1) of rule 13 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type of residence having the earliest date of priority for that type of residence, subject to the following conditions:—

- (i) The Director shall not allot a residence of a type higher than to what the applicant is eligible under rule 5.
- (ii) The Director shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than to what he is eligible under rule 5.
- (iii) The Director, on request from an applicant for allotment of a lower category residence may allot to him a residence of one type below for which the applicant eligible under rule 5 on the basis of his priority date for the same.

(2) The Director may cancel the existing allotment of an officer/official and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of type next below the type of residence in occupation of the officer/official if the residence in occupation of the officer is required to be vacated in public interest.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer/official under sub-rule (1), be offered simultaneously to other eligible officers/officials in the order of their priority dates.

8. *Adhoc allotment on out of turn basis.*—Notwithstanding the provisions of rule-7, *ad hoc* allotment on out of turn basis may be made by the House Allotment Committee to an officer/officials on the following grounds :—

(1) On the following type of illness :—

(i) Physically handicapped Government employees in the following cases :

(a) The Blind i.e. those who suffer from either of following conditions :

(i) Total absence of sight.

(ii) Visual Acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snell) in the better eye with correcting lenses.

(iii) Impression of the field of the vision subtending an angle of 20 degrees or worse.

(b) The Deaf—Those in whom the sense of hearing non functional for ordinary purposes of life. They do not hear, understand sounds at all even with amplified speech. The cases include in that category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

(c) The orthopaedically handicapped, that is, those who as a result of their orthopaedic deformity find it very difficult to move freely; or

(ii) Heart ailment for self only (heart ailments having symptoms of Grade III and IV which includes serious disabilities like Angina Grade III and IV or congested cardiac failure Grade III and IV or Malignant Hypertension with symptoms of Grade III and IV); or

(iii) Tuberculosis (Pulmonary tuberculosis in active phase with risk to other) and Cancer, of self, spouse and dependent children.

(2) In the event of death or retirement of a Government servant, to the wife/husband or son or unmarried daughter, provided that the retired or the deceased Government servant was in occupation of Government accommodation at the time of retirement or death. Such allotment shall not be made in a category higher than a category to which the ward of the deceased or retired Government servant is entitled.

(3) In the event of transfer, deputation on foreign service sponsored by the Government and study leave of more than one year of an allottee, to the spouse of such employee according to his/her entitlement in case the spouse is in Government service and posted at the same station.

(4) In the event of officer occupying an earmarked house and is transferred to another post at the same station or to another station.

(5) An officer/official who after completing of their full tenure in the Districts of Lahaul and Spiti, Kinnaur and Pang T Tehsil of Chamba district are transferred.

(6) Personal staff i.e. one out of the Personal Assistants/Private Secretaries etc. of the Ministers.

(7) Where exigencies of services so warrant.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (7), an officer/official who owns a house either in his own name or in the name of any member of his family at or near the station of his/her posting, shall not be eligible for *ad hoc* allotment on out of turn basis.

(9) (i) State Level Correspondents of National Dailies, State Level Press Correspondents of other daily newspapers for whom shall take into consideration the circulation and other factors justifying the allotment of Government accommodation, and who are accredited to Himachal State and whose case has been recommended by the Director of Public Relations Himachal Pradesh may be considered for allotment of one category below house, and in any case not above type-IV, to which entitled according to basic pay only i.e. excluding the element of D.A., at Shimla only. Such allotment shall only made to the correspondents who do not own a house in his name or any member of his family:

Provided that in case a correspondent who has already been allotted Government residential accommodation acquires a house of his own at the place shall have to surrender the allotted accommodation immediately and in case he or any member of his family acquires



or inherits or constructs any house or part of the house he shall have to surrender the allotted accommodation immediately thereafter and an affidavit to this effect shall be obtained at the time of allotment from such correspondent:

Provided further that an allottee of accommodation under this sub-clause shall pay the licence fee as per provisions of these rules and shall also pay the house rent allowance paid to them by the Newspaper or News Agency in which he is employed.

(ii) Priority for allotment shall be from the date of receipt of application for the allotment of accommodation.

(iii) Only one house shall be allotted to one News Agency or Newspaper:

Provided that *ad hoc* allotment on out of turn basis under these rules shall not exceed 50% of the houses available in each category. Type-IV and above houses will be bracketted together for determining the percentage and allotment made under sub-rules (2), (3) and (9) of this rule shall not form part of the percentage of allotments made under this rules.

9. *Non-acceptance of allotment or failure to occupy the allotted residence after acceptance.*—(1) If an officer/official fails to accept the allotment of residence of the type to which he is entitled within five days or fails to take the possession of that residence after allotment within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter.

(2) If an officer/official occupying a residence of a type lower than the one to which he is eligible is allotted a residence of the type for which he is eligible under rules, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

- (a) That such an officer/official shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter for the higher type of accommodation;
- (b) While retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under F.R. 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher for a period he/she has been debarred for allotment for a period of one year for which he has been debarred for higher type of accommodation.

(3)(a) An officer/official may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director at least 10 days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director or the date specified in the letter whichever is later. If he fails to give due notice, he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days:

Provided that the Director may accept the notice for a shorter period.

(b) An officer/official who surrenders the residence under clause (a) of sub-rule(3) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

A surrender notice is not necessary in the following types of cases:—

- (i) When an officer/official in occupation of a lower type of residence than his entitlement is allotted a residence of the type to which he/she is entitled.
- (ii) When an officer/official on his re-employment is found to be entitled to a lower type of accommodation.
- (iii) When an officer/official is given change of residence to another in the same type.
- (iv) When the residence in occupation of an officer/official is required for a public purpose, repairs or for demolition.
- (v) When the allotment of the residence in occupation is cancelled/deemed to be cancelled under the provisions of the allotment rules.
- (vi) When the son/daughter etc. of retiring/deceased allottee gets alternative accommodations.

10. *Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention:—*  
 (1) An Allotment shall be effective from the date on which the house is occupied or five days from the date of allotment letter which is earlier and shall continue in force till:—

- (a) The expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office in Himachal Pradesh.
- (b) It is cancelled by the Government or it is deemed to have been cancelled under provision of these rules.
- (c) It is surrendered by the officer, or.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of one of the event specified in column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof; provided that the residence is required for the *bonafide* use of the officer or members of his family:—

Event 1	Permissible period of retention of the residence 2
(i) Resignation, dismissal, removal or termination of service or unauthorised absence without permission.	4 months
(ii) Retirement or terminal leave	4 months
(iii) Transfer outside the station	2 months or upto the date of allotment at new place of posting, whichever is earlier.
(iv) Death of the allottee	1 year

1

2

(v) On proceedings on foreign service in India.	2 months
(vi) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	6 months
(vii) Transfer of an officer occupying an earmarked house.	1 month from the date of handing over charge.
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave.	For a period of leave, not exceeding four months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave.	For the full period of leave subject to maximum of four months inclusive of the permissible at the time of retirement.
(x) Deputation outside India.	For the full period of deputation but not exceeding one year.
(xi) Study leave in India or abroad.	For the period of leave but not exceeding six months.
(xii) On proceeding on training.	For the full period of training
(xiii) Maternity leave.	For a period of maternity leave plus the leave granted in continuation subject to maximum of five months.
(xiv) Leave on medical grounds, requiring hospitalisation beyond four months.	Full period of leave

*Explanation 1.*—The period permissible on transfer mentioned against items (iii), (vi) and (vii) shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave if any sanctioned to and availed of by the officer/official before joining duty in new office.

*Explanation 2.*—Where an officer/Official is on medical leave without pay and allowances he may retain his residence by virtue of the concession under item (xiv) of the table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee more than two months, the allotment shall stand cancelled.

*Explanation 3.*—Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods.

*Explanation 4.*—An officer who has retained the residence by virtue of the concession under items (i) and (ii) of the above below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within a period specified in the said table be entitled to retain that residence under these rules, provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he may be allotted a residence of the type to which he is entitled.

Provided that an officer/official in special cases may be allowed by the Secretary, Department in G.A.D. to retain a residence on payment of twice the pooled standard licence fee for a period not exceeding six months beyond the period permissible under sub-rule (2) above. Provided further that in the cases of extreme compassionate grounds, an officer/official may be allowed further period of retention by the Chief Secretary, Himachal Pradesh Government:

Provided further that if any allottee is transferred or retires in the mid-academic session and his/her children are receiving education in School/College or University, as the case may be, at the place of his/her present posting, the allottee may be allowed by the Department in G.A.D. on the basis of merits of each case to retain the accommodation till that current academic year is completed subject to production of certificate from the concerned institution to this effect. Licence fee chargeable in such case will be two times of the pooled standard licence fee for the period beyond the concessional period permitted under the rules in cases of retirement and transfer, as the case may be :

Provided further that in case of officer/official who proceeds on foreign service abroad and on deputation out side India, study leave in India and abroad, the department concerned of any officer/official are required to make the provision in the terms and conditions of such orders with prior approval of the Government in General Administration Department that he/she can retain the Government residential accommodation, if any allotted only for the *bonafide* purpose of his/her family as per provisions of the rules :

Provided further that officers/officials in the events mentioned above shall furnish an affidavit that that the Government accommodation allotted to him/her shall be used only for the *bonafide* purpose of his/her family and in case it is found at any time that the accommodation is not used for the *bonafide* purpose of his/her family, the Government may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him/her, cancel the allotment of residence.

(3) If immediately after retirement the officer/official of the Himachal Pradesh Government has not availed the permissible period of retention, he may be allowed the concessional period of retention as provided in sub-rule (2) after the completion of re-employment. In the case the officer/official has been allowed part of the permissible period of retention before re-employment, he may be allowed the remaining part of the permissible period of retention after termination of the re-employment.

(4) The officer/official who are appointed by the Himachal Pradesh Government on a tenure post shall not be eligible for concession allowed under sub-rule (2) and such officer/official shall vacate the accommodation allotted to him within a period of 15 days after the tenure of his post is over.

11. *Payment of licence fee.*—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eight day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(2) An officer/official who, after acceptance fails to take possession of the accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days or upto the date on which he withdraws his acceptance, whichever is later.

(3) Where an officer/official who is in occupation of a residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for two days after occupation of the new house.

12. *Personal liability of the officer/official for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers/officials:—*

(1) The officer/official to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by the Government during the period for which the residence has remained under his occupation.

(2) Where the officer/official to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a surety bond in the form prescribed in this behalf by the Himachal Pradesh Government with a surety who shall be a permanent Government servant serving under Himachal Pradesh Government for payment of licence fee and charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service, withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Government, be deemed to have been cancelled with effect from the date of the event.

13. *Change of residence.*—(1) An officer/official to whom a residence has been allotted under these rules, may apply for a change of residence within the same type. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of a residence during his stay at a station:

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(2) Changes shall be offered in the order of receipt of applications for the same in the office of Director of Estates/Estate Officers.

(3) If an officer/official fails to accept a change of residence offered to him within eight days of the receipt of such order/offer or allotment, he shall not be considered again for a change of allotment of that type.

(4) A second change may be allowed for exceptional reasons by the House Allotment Committee.

14. *Change of residence in the event of death of member of the family.*—Notwithstanding anything contained in rule 13, an officer/official may be allowed a change of residence on the death of any member of the family if he applies for a change within three months of such occurrence; provided that the change will be given in the same type of residence already allotted to the officer/official.

15. *Mutual exchange of residence.*—Officer/official to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers/officials are reasonably expected to be on duty at the same station and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

16. *Transfer to non-family station.*—If an officer/official is transferred where he is not permitted or advised by the Government to take his family with him and the residence allotted to

him under these rules, is required by the family for *bonafide* use, he may be allowed, on request, to retain the residence on payment of normal licence fee.

**17. Sharing of accommodation.**—(1) No officer/official shall share the residence allotted to him including any of the out houses, garages and stables appurtenant thereto unless authorised to do so by the Government.

(2) Any sharing of accommodation with close relatives shall not be treated subletting/sharing. The following relations will be treated as close relations viz. father, mother, brothers, sisters, grand father, grand mother, grand sons, grand daughter, uncles, aunts, first cousins, nephews, nieces directly related by blood to allottees, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law and any other relationship established by legal adoption.

**18. Power to cancel allotment.**—(1) If any officer/official to whom a residence has been allotted sublets the residence or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connections or commits any other breach of rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises for any purposes which the Government considers to be improper or conducts himself in a manner which in the opinion of the Government is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement, with a view to securing a allotment, the Government may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him cancel the allotment of the residence.

*Explanation.*—In this sub-rule the expression 'officer/official' include unless the context otherwise require, a member of his family and any other person claiming through the officer/official.

(2) If the officer/official has failed to notify the information to the Director/Estate Officer as provided under rule 3 or while so notifying the information has in any application or statement suppressed any material fact, the Director may cancel the allotment.

(3) If any officer/official sublets a residence allotted to him or any portion thereof in contravention of these rules, he may without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged damages.

(4) Where action to cancel the allotment is taken on account of subletting of the premises by the allottee, a period of 7 days shall be allowed to the allottee or any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of 7 days from the date of order for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(5) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the neighbours, the officer at the discretion of the Government may be allotted another residence, in the same type at any other place.

**18A. Charging of damages from unauthorised occupants of general pool residential accommodation and recovery of licence fee.**—(1) Whereafter an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains, in occupation of the officer/official to whom it was allotted or a person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges calculated at the rate of Rs. 4.00 per sq. foot.

*Explanation.*—'services' include conservancy, common light and common water facility.

(2) In the case of retiring officers/officials the leave encashment benefits will be released only if they have vacated the Government accommodation allotted to them while in service. The amount of leave salary shall be drawn by the Drawing and Disbursing Officer immediately on retirement and the same shall be put in F. D. R. for four months in the name of retiree, pledged with the Drawing and Disbursing Officer as a security for damages under sub-rule (1).

19. *Maintenance of separate pools for certain categories.*—(1) Notwithstanding anything contained in these rules the following separate pools shall be maintained, namely:—

- (i) Lady Officer's/official's pool
- (ii) Transit pool
- (iii) Tenure Officer's/Official's pool.

(2) The number and types of residences to be placed in these pools shall be determined by the Government from time to time.

(3) The *inter-se-seniority* of the officers/officials eligible for the allotment of residences under this rule shall be determined in the following manner, namely:—

- (a) In the Lady Officer's/official's pool, the Lady officers/officials entitled to allotment of accommodation in the type next below the type to which they are entitled under the provision of rule 5, on the basis of the priority date on which each such officer/official become eligible for the type of residence in that pool.
- (b) In the Tenure Officer/official Pool, on the basis of the date from which each such Officer/official began to draw emoluments pertaining to the type to which he is to be considered for allotment.
- (c) In the Transit Pool, the officer's/official's, (i) who join their station of new posting on transfer from another station, (ii) who is victim of natural calamities like heavy rains, heavy snow fall, wind and storms, earthquakes and fire accidents etc., (iii) who has been evicted from private house and whose private house has been acquired by the Government in the public interest, (iv) whose house has been collapsed or gutted in fire, and (v) persons in whose cases their are compassionate circumstances of an extreme nature, shall be entitled to transit pool accommodation, on the basis of seniority from the date of receipt of his/her application. An application for transit pool accommodation shall, however, remain valid for six months only.

(4) (a) In the Lady Officer's/Official's pool all Lady Officers and officials eligible for the allotment from the general pool under the rules, are eligible for allotment from Lady Officers/Officials pool.

(b) In the Transit Pool, all officers/officials who are eligible for allotment from general pool under the rules, are eligible for allotment from transit pool on the grounds mentioned in clause (c) of sub-rule above.

(c) In the Tenure Pool, all officers/officials on return from deputation from

Government of India, officers posted outside State headquarters for a particular tenure such as D. C.'s, Sessions Judges, Sub-Divisional Officer (Civil) etc. on transfer back to State Headquarters are eligible for allotment from the Tenure Pool.

(5) (a) The allotment in the Lady Officer's/Official's Pool and Tenure Officer's Pool shall remain valid for the period they remain posted at the Station.

(b) The allotment of transit Pool accommodation shall be valid for one year and further can be extended for another six months; provided the officer/official remain posted at the same station.

(6) (a) The licence fee in respect of Lady Officer's/Official's Pool and Tenure Officer's Pool shall be recovered under the provisions of the F. R. 45-A chargeable in respect of general pool accommodation.

(b) The licence fee of Transit Pool Accommodation shall be charges as under :—

- |   |                 |
|---|-----------------|
| (i) Single room accommodation with common latrines (for Class IV employees).            | .. Rs. 20/- PM  |
| (ii) Single room accommodation with separate latrines (for Class III and IV employees). | .. Rs. 35/- PM  |
| (iii) Double room accommodation (for class III employees).                              | .. Rs. 65/- PM  |
| (iv) Double room accommodation (for class I and II officers.)                           | .. Rs. 100/- PM |

*Note.*—Any other facility provided in the accommodation such as geyser and furniture etc., the charges thereof shall be charges extra. The allottee shall be personally responsible for the payment of water and electricity charges direct to the concerned Department/Corporation.

20. *Continuance of allotment made prior to the issue of these rules.*—Any valid allotment of residence which is in force immediately before commencement of these rules, under the rules then in force, shall be deemed to be allotment duly made, under these rules notwithstanding the fact that the official to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under the relevant rules and all the proceedings provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

21. *Interpretation of rules.*—If any question arises as to interpretation of these rules, the decision of the Government shall be final.

22. *Delegation of powers or functions.*—(1) The Government may delegate any or all the powers conferred upon it except the power to make or amend the rules, by the rules to any officer under its control, subject to the conditions as it may deem fit to impose.

(2) The Director may further delegate all or any of the power exercisable by him to the various Estate Officer of the respective Districts:

Provided that the powers under rule 24 of these rules shall not be delegated to any officer.

23. *Allotment to officer/official entitled to rent free and Departmental Pool Accommodation.*—Officers/officials who are entitled to rent free accommodation and officers/



Officials whose department has their own departmental pool accommodation shall not be eligible for allotment from the general pool accommodation:

Provided that at the Stations where the Departmental pool accommodation for the officers/officials does not exist he will be considered along with other employees at that station for the allotment of accommodation from the general pool. Officer/Official entitled to rent free accommodation will be considered for allotment from general pool subject to the condition that if they are allotted accommodation the licence fee will have to be paid by the concerned department.

**24. Relaxation of rules.**—Government may, for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of these rules in the public interest or in cases of extreme compassion.

**25. Repeal and Savings.**—(1) The allotment of Government Residences (General Pool) in Himachal Pradesh Rules, 1986 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, any order or allotment made, any action taken or thing done shall be deemed to have been taken or done, under corresponding provisions of these rules.

By order,

S. S. NEGI,  
Commissioner-cum-Secretary (GAD),  
to the Govt. of H. P.